


न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी घनश्याम योगी बनाम नगर परिषद सवाईमाधोपुर जरिये आयुक्त नगर परिषद
किरम प्रकरण- अपील प्रकरण संख्या 104/2019 (RCMS NO 2019/00151)

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | 1/10/2019 जज के हुकम के प्रमाण के साथ सुनी |
|------------|--|---|
| 11.3.2020 | <p>पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। तलवी मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त होने पर बहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी।</p> <p>दौराने बहस स्वयं अपीलान्त जो कि अधिवक्ता है के द्वारा कथन किया कि आदेश जैर अपील आदेश क्रमांक/न.प.स.मा./वि.शा./2019-20/7022 दिनांक 25.9.2019 विधि विरुद्ध एवं खिलाफ कानून होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि आयुक्त महोदय द्वारा नगरपालिका अधिनियम,1959 के नियमों को समझने में अहम भूल की है। अपीलान्त द्वारा दिनांक 16.12.2016 को कयशुद्धा भूमि के तामीर निर्माण स्वीकृति हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जो राजस्व रिकार्ड में ख0न0 2144 गैर मु. आबादी कस्बा आलनुपर में स्थित है एवं यह भूमि पूर्व से ही निर्मित थी जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने से पुनः निर्माण की स्वीकृति चाही गयी थी जिसके लिए नगर परिषद सवाईमाधोपुर ने अपीलान्त स 1500/-रु जमा कर आपत्ति नोटिस जारी किये एवं विधि सलाहकार की राय ली गयी जिसमें विधि सलाहकार द्वारा अंकित किया कि अन रजिस्टर्ड दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 14.10.2016 के आधार पर निर्माण स्वीकृति जारी की जा सकती है अथवा नहीं यह नगर परिषद सवाईमाधोपुर विभागीय निर्देशों के आधार पर गुणावगुण पर निर्णय लेकर स्वयं तय करे। इसी दौरान रफीक मोहम्मद की आपत्ति प्राप्त हुई थी जिसको बाद सुनायी दिनांक 7.6.2017 को खारिज करते हुए तामीर स्वीकृति हेतु निर्देश दिया गया कि तामीर स्वीकृति चाही गयी भूमि का पट्टा नहीं होने से प्रकरण को लंबित करने के आशय से बिना विधिक राय एवं बिना विधिक प्रावधानों के स्वेच्छा से नियमों की अवहेलना करते हुए 2000/-रु जमा करवाये, जबकि तामीर स्वीकृति चाही गयी भूमि नगर परिषद के प्रभाव में आने से पूर्व ग्राम पंचायत क्षेत्र में आबादी में स्थित थी एवं पूर्व से ही पुख्ता निर्माण शुद्धा थी जिसका सन् 1939 में पंजीकृत पत्र से पट्टा जारी किया हुआ है। दिनांक 7.8.2018 को विधि सलाहकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी राय दी गयी थी कि नगर परिषद अपीलार्थी को तामीर स्वीकृति देने में सक्षम है परन्तु दिनांक 25.9.2019 को अपीलार्थी का आवेदन बिना किसी आधार के यह अंकित करते हुए निरस्त कर दिया कि पत्रावली में किसी प्रकार का पट्टा नहीं है। अतः निर्माण स्वीकृति नहीं दी जा सकती है जबकि प्रारम्भिक स्थिति दिनांक 14.10.2016 में विक्रय नामा का स्पष्ट वर्गन किया हुआ है बावजूद उसी स्थिति के आधार पर तीन वर्ष तक पत्रावली को लंबित रखा एवं विभिन्न विभागों की राय एवं स्पष्ट दिशा निर्देशों के बाद भी जानबूझकर विधि के विपरीत तामीर स्वीकृति आवेदन निरस्त किया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>वकील रेषपो. द्वारा दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूखण्ड का नियमन एवं तामीर स्वीकृति चाही गयी है उक्त भूखण्ड के स्वामित्व स संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, तथा उक्त भूखण्ड को लेकर श्री रफीक अहमद द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जो नगर परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा निरस्त कर दिये जाने पर आपत्तिकर्ता श्री रफीक अहमद पुत्र श्री नूर मोहम्मद मुसलमान द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश सवाईमाधोपुर के न्यायालय में वाद पेश किया है जो वर्तमान में जैरकार है। उक्त भूखण्ड को लेकर न्यायालय में वाद विचाराधीन होने एवं अपीलान्त के पास स्वामित्व संबंधी दस्तावेज नहीं होने के कारण निर्माण स्वीकृति नहीं दी गयी है।</p> <p>वकील उभय पक्षों को सुनने एवं नगर परिषद की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम तो अपीलान्त के पास जिस भूखण्ड की निर्माण स्वीकृति चाही जा रही है उसके स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज यथा पट्टा इत्यादि नगर परिषद में प्रस्तुत नहीं किया ओर ना ही इस न्यायालय में पेश किया है इसके अतिरिक्त उक्त भूखण्ड के संबंध में आपत्तिकर्ता श्री रफीक अहमद द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर रखा है जो वर्तमान में जैरकार न्यायालय है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्त खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 11.3.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> | |


 (डॉ०एस०पी०सिंह)
 जिला कलेक्टर
 सवाई माधोपुर

